

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2018

लादी आयु वर्ष पुत्री श्री सुवा जाति माली निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
—प्रार्थीयां

बनाम

- 1.गोपाल पुत्र श्री सुवा
- 2.बालू पुत्र श्री सुवा
- 3.माम जाति माली निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला-अजमेर
- 4.सीताराम पुत्र श्री देवीलाल जाट
- 4.बाबूलाल पुत्र श्री बालूमल जाति सिंधी
- 5.ठाकुरदास पुत्र श्री बालूमल जाति सिंधी
- 6.ज्ञानचंद पुत्र श्री सुजान मल जाति अग्रवाल
- 7.ज्ञानप्रकाश पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जाति टांक
तमाम निवासीगण केकड़ी जिला अजमेर।
- 8.राजस्थान सरकार जंरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।
- 9.उप पंजीयन अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

—अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम

उपस्थित :- श्री सांवरलाल चौधरी - वकील प्रार्थी
श्री चेतन धाबाई - अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2
श्री राजेश शर्मा - अप्रार्थीगण संख्या 4 से 7

आदेश

दिनांक 22-11-2019

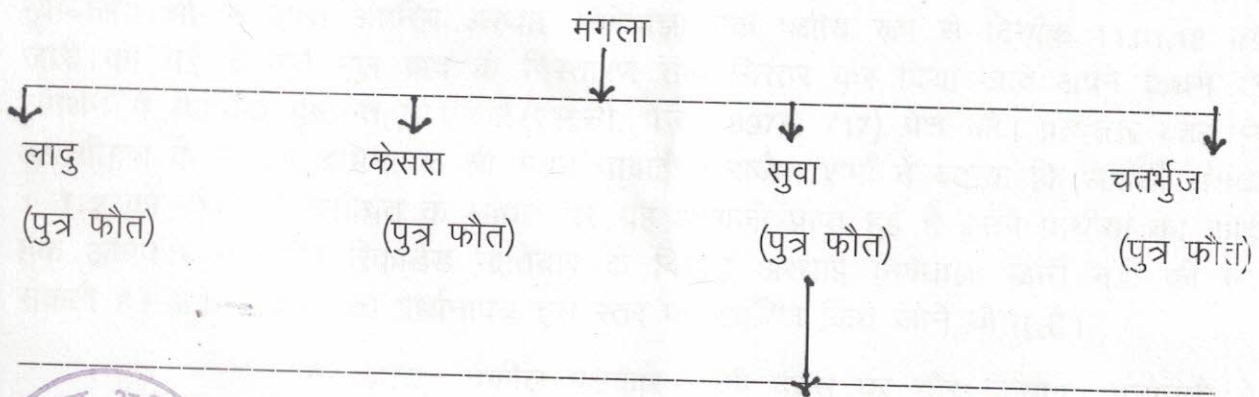
संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयां ने एक वाद अंतर्गतधारा 88,89,188,53,209 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का पेश किया तथा उसके साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी की जमाबंदी संवत् 2069-72 में निम्न वर्णित आराजीयात स्थित है ।

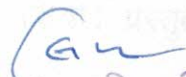
खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
473-425	4984	0.26	बारानी 2
	4985	0.50	
	4986	0.17	
	4984	0.30	
	4991	1.12	
	4992	0.03	
	5238	0.80	

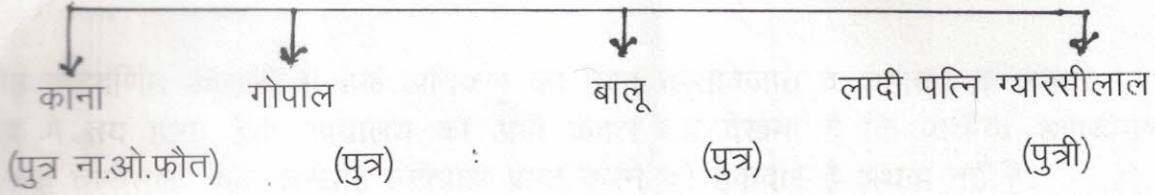


उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

गौरु की मृत्यु के बाद वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 के नाम राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई है। वर्णित आराजीयात जो प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी और संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसे प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं और बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है तथा उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीयां एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक इंच पर संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन उक्त आराजीयात का बँटवारा नहीं होने के कारण आये दिन कब्जे काश्त में मुद्दा होता है तथा सरकारी योजनाओं का भी फायदा नहीं मिलता है इसलिए बँटवारा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। प्रार्थीयां ने दिनांक 23.12.17 को अप्रार्थीगण 1 व 2 को ऐसा नहीं करने बाबत निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने खुल्लम खुल्ला धमकियां दी कि हम तेरे को तेरे हक हिस्से की पुश्तैनी आराजीयात से वंचित करके रहेंगे एवं जबसे बेदखल कर देंगे अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे वादवर्णित पुश्तैनी आराजीयात में से प्रार्थीयां के हिस्से की आराजीयात से प्रार्थीयां को बेदखल नहीं करे तथा न ही आराजी को रहन बेचान बक्षीस करे अप्रार्थी संख्या 8 व 9 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात का बिना विधिक बँटवारा हुए विक्रय पत्र वसीयत व अन्य हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेजात का पंजीयन नहीं करे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग करने में सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीयां को अजहद क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब की प्रति वकील प्रार्थीयां को दिलवायी गयी। जवाब में अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता सुवा पुत्र मंगला की आराजी नहीं है इसलिए पुश्तैनी होना अस्वीकार है। प्रार्थीयां द्वारा प्रार्थना पत्र में जो सजरा प्रस्तुत किया गया है जो अस्वीकार किये जाने योग्य है प्रार्थीयां व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का सजरा निम्न प्रकार है:-




 उपखण्ड अधिकारी
 केकडी (जिला-अजमेर)




गौरु पुत्र काना की लगभग 75 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गयी थी तब उसकी एक मात्र लड़की ग्यारसी ही थी प्रार्थीयां एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जन्म भी नहीं हुआ था। वादवर्णित आराजी की एक मात्र मालिक ग्यारसी ही थी। वादवर्णित आराजीयात की एक मात्र खातेदार ग्यारसी पत्नि मांगीलाल पुत्री गौरु ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करवाला थी थी तथा ग्यारसी की मृत्यु के बाद वसीयत के आधार पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जरिये नामा0 करवा लिया गया था। इस प्रकार सम्पूर्ण आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का हक मालिक व खातेदारी है। प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नहीं नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 3 व 4 से 7 ने भी अपने अपने जवाब में वादवर्णित आराजीयात को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से जरिये रजिस्टर्ड क्य करना जाहिर किया तथा प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की। सभी अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

प्रार्थीयां के विद्वान वकील श्री सांवरलाल चौधरी ने बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि आराजी वादवर्णित पुश्तैनी आराजीयात है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ साथ एवं तीनों का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा प्रत्येक का है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलीभगत करके अपने नाम करवा ली है तथा आराजी वादवर्णित को अन्य व्यक्तियों के नाम करवाना चाहते हैं अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे किये वाद वर्णित आराजी के प्रार्थीयां के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा ना ही प्रार्थीयां के हिस्से की आराजीयात को बेचान बक्षीस करे। व ना ही प्रार्थीयां के हिस्से की भूमि में प्रार्थीयां के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे यानि हर प्रकार से मनमुह व बाज रखा जावे साथ ही अप्रार्थी संख्या 9 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजीयात के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले विक्रय पत्र बक्सीश दान पत्र इत्यादि का पंजीयन नहीं करे। प्रार्थीयां के पक्ष मांग0 न्यायालय श्रीमान् द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय रूप से दिनांक 11.01.18 को जारी की गई है उसे मूल वाद के निस्तारण तक निरंतर कर दिया जावे अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे.(एस.सी. पेज 697 से 717) पेश की। प्रत्युत्तर बहस में अप्रार्थीगण के लायक अभिभाषक श्री चेतन धाबाई व राजेश शर्मा ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर यह आराजी प्राप्त हुई है इसमें प्रार्थीयां का कोई हक अधिकार नहीं है। रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

मेरे द्वारा वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजीर का ससम्मान अध्ययन किया




 उपखण्ड अधिकारी
 केकडी (जिला-अजमेर)

गया वादवर्णित आराजी मे हक अधिकार का प्रश्न दस्तावेजात व शहादत के आधार पर मूल वाद मे तय होगा इस न्यायालय को अभी केवल यह देखना है कि प्रार्थीयां-अप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं?

1.प्रथम दृष्टया केस:- ग्राम केकड़ी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जमाबंदी संवत् 2069-72 के अनुसार आराजी वादवर्णित मे प्रार्थीयां का प्रथम दृष्टियां केस साबित नहीं होता है।

2.सुविधा का संतुलन-अप्रार्थीगण आराजी वादवर्णित के रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध प्रार्थीयां अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीयां के पक्ष मे नहीं पाया जाता है।

3.अपूर्णनीय क्षति:-प्रार्थीयां,प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार नहीं है। तथा अपना कब्जा काश्त साबित करने के लिए भी कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने मे सफल नहीं हुई है। ऐसी स्थिति प्रार्थीयां को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने के फलस्वरूप अपूर्णनीय क्षति किस प्रकार हो सकती है सिद्ध नहीं कर पायी है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीयां अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों आवश्यक बिन्दु प्रार्थीयां अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल नहीं हुई है अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदार नोकर चाकर इत्यादि को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीयां के हिस्से के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा पहुँचाने, बेचान बक्षीस करने व विक्रय पत्र पंजीयन करवाने से रोकने बाबत् प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नहीं करता है। हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे तय होगा। खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी ककड़ी
ककड़ी (जिला-अजमेर)

